

THE HINDU 29 MARCH DANGEROUS PRECEDENT

गोलन हाइट्स

संदर्भ – अमेरिका ने इजरायल के गोलन संप्रभुता का समर्थन किया।

- गोलन हाइट्स पहाड़ियां की भौगोलिक स्थिति देखें तो इसके पूर्व में सीरिया पश्चिम में इजरायल उत्तर में लेबनान और दक्षिण में जार्डन है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तथा यह इजरायल और सीरिया के बीच का विवादित क्षेत्र है। दरअसल ये दक्षिण-पश्चिमी एशिया से लगा एक पहाड़ी इलाका है। यह पूरा क्षेत्र 1800 वर्ग किमी. के दायरे में विस्तृत है।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम-

- 1967 से पहले गोलन पहाड़ियां सीरिया का भाग थी लेकिन 1967 में अरब-इजरायल संघर्ष हुआ और इजरायल ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि कोई भी देश इस बात को मान्यता नहीं देता है, कि गोलन हाइट्स इजरायल का भाग है।
- 1973 में मध्य-पूर्व के युद्ध के दौरान सीरिया ने इस क्षेत्र को वापिस पाने की कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
- 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। गोलन हाइट्स में इजरायल और सीरिया के सीज फायर की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में शांति सेना तैनात की।
- 1967 के युद्ध का कारण इजरायल और फिलिस्तीन के बीच होने वाले सीमा-विवाद थे। इसके अलावा अन्य मध्य पूर्व देशों की गतिविधियां जैसे – मिस्र द्वारा लाल सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर प्रतिबंध लगा देना भी शामिल था।
- 1967 में इजरायल ने मिस्र की राजधानी काहिरा पर आक्रमण किया। मिस्र पर आक्रमण के बाद जार्डन ने इजरायल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जबकि सीरिया ने युद्ध में शामिल होते हुए अपनी सेना को मिस्र के निर्देशन में दे दिया। सीरिया के बाद इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया यमन भी मिस्र के समर्थन में आ गए।
- अरब देश को इजरायल ने अपने सैनिक कुशलता के कारण काफी नुकसान पहुंचाया। और उनके कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इसी क्रम में इजरायल द्वारा सीरिया की गोलन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से 10 जून 1967 को अरब देशों और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू हुआ।
- 1981 में इजरायल ने गोलन हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा करते हुए इस क्षेत्र में अपने कानून, प्रशासन व न्यायिक प्रक्रिया को लागू किया।

इजरायल व अरब देश के संबंध

- 1948 में हिटलर ने जब यहूदियों पर अत्याचार किए तब अन्य राष्ट्रों ने यहूदियों को अपनी जमीन और अपने देश में जगह देने की बात की और 14 मई 1948 को इजरायल के रूप में अपना देश मिल गया।
- इजरायल की स्थापना के बाद अन्य पड़ोसी देशों ने उसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, चारों ओर से अरब देशों से घिरा इजरायल अपनी सैन्य ताकत के बल पर विरोधी देशों पर भारी रहा है।
- नए देश के रूप में स्थापित इजरायल पर जल्द ही अरब देशों ने आक्रमण किया ताकि इजरायल से यहूदियों को निकाला जा सके, लेकिन वे सफल न हो सकें, आखिरकार 1967 में इजरायल व अन्य अरब देशों में युद्ध छिड़ गया।

अरब देशों ने इजरायल को समर्थन देने वाले देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जो 1974 तक जारी रहा।

- 1977 में शांति समझौते के तहत मिस्र के राष्ट्रपति ने इजरायल को पहली बार मान्यता दी।
- खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका की पहल पर 1991 में मैड्रिड शिखर सम्मेलन हुआ। 1993 में नार्वे के शहर ओस्लो में भी शांति वार्ता हुई। 1994 को इजरायल और PLO के बीच काहिरा में सहमति बनी। हालांकि पिछले कुछ समय में मिस्र और जॉर्डन ने इजरायल के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया है लेकिन अभी भी अरब देश इजरायल से बेहतर संबंध हेतु कदम उठाने से हिचकते हैं।

अमेरिका व इजरायल संबंध-

- अमेरिका से मिले समर्थन ने इजरायल और अमेरिका को नजदीक ला दिया। अमेरिका द्वारा इजरायल की राजधानी के रूप में यरूशलम को भी मान्यता प्रदान की गई। अमेरिका का यह कदम सीरिया व इजरायल के मध्य शांति प्रक्रिया की समस्याओं को बढ़ा सकता है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मानदंड व आम सहमति का भी उल्लंघन करता है।
- आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संप्रभुता पर कायम है, प्रत्येक राष्ट्र को सैन्य व अधिकारों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में समान माना जाता है। गोलन हाइट्स के मुद्दे भी इजरायल व सीरिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के साथ सुलझाना चाहिए, लेकिन अमेरिका द्वारा इजरायल को गोलन हाइट्स की संप्रभुता की मान्यता देने के निर्णय ने शांतिपूर्ण निदान की संभावना को मुश्किल बना दिया है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. 'गोलन हाइट्स' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए-
 1. गोलन हाइट्स के पूर्व में इजरायल पश्चिम में सीरिया उत्तर में लेबनान और दक्षिण में जॉर्डन है।
 2. अरब इजरायल संघर्ष ने पश्चिम एशिया में इजरायल की शक्ति को स्थापित किया।
 3. इजरायल गोलन हाइट्स पर अपनी संप्रभुता स्थापित करते हुए अपने अनुसार कानूनों को संचालित कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2
- (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय सामरिक विवादों को सुलझाने में किस हद तक सफल रही है? इस कथन के संबंध में गोलन हाइट्स के वास्तविक मालिकाना हक पर अमेरिका द्वारा इजरायल को समर्थन देना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। व्याख्या कीजिए।

(THE SHAPE OF AN URBAN EMPLOYMENT)

शहरी रोजगार गारंटी के स्वरूप में बदलाव

संदर्भ-

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% तक पहुंच गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की समस्या विशेष रूप से भारत के शहरों व कस्बों में बढ़ी है। बेरोजगारी के अलावा कम मजदूरी की भी समस्या है। शहरी भारत में बहुसंख्यक आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, इसलिए भारत में शहरी रोजगार के संकट को नकारा नहीं जा सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट है।

शहरी रोजगार कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता क्यों है?

- राज्य और केंद्र दोनों के लिए कस्बे 'विकास इंजन' के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए 1997 में 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' जैसे कार्यक्रमों में शहरी वेतन व रोजगार को शामिल किया गया जिसमें कौशल व उद्यमिता पर भी ध्यान दिया गया।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 4041 शहर व कस्बे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'स्मार्ट सिटी' व 'अटल मिशन और शहरी परिवर्तन (AMRUT)' जैसे प्रोग्राम से इनमें से बहुत कम शहर व कस्बे लाभान्वित हो रहे हैं। अधिकांश कस्बे वित्तीय व मानव बल कौशल की कमी के साथ बुनियादी समस्याओं जैसे- अनियंत्रित शहरीकरण के साथ शहरी पर्यावरण के क्षरण से जूझ रहा है।

उपाय- इस चुनौती से निपटने के लिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

- शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके तथा शहरों की बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में सुधार हों। शहरों में युवाओं को कौशल प्रदान करना चाहिए ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई जो कुशल व कुशल श्रमिकों हेतु प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान करने के लिए की गई।

शहरी रोजगार गारंटी का स्वरूप क्या हो?

- सतत रोजगार के माध्यम से कस्बों को मजबूत बनाया जाये।
- अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 'सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट' रिपोर्ट के अनुसार शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए जो अनुच्छेद-21 के अंतर्गत जीवन की गारंटी के अधिकार को सुनिश्चित करेगा।

- शहरी व कस्बों के विकास के लिए केंद्र व राज्य से वित्त उपलब्ध कराया जाय तथा शहरी स्थानीय संस्थाओं द्वारा मजदूरी को विकेन्द्रीकृत तरीके से वितरित किया जाएगा।
- 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के साथ-साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्र के कौशल विकास व रोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

शहरी जॉब का स्वरूप-

1. **सार्वजनिक कार्य** - शहरी अनौपचारिक श्रमिकों हेतु सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़क, फुटपाथों और पुलों के निर्माण व रखरखाव के लिए वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलनी चाहिए।
2. **ग्रीन जॉब्स** - शहरी क्षेत्रों में ग्रीन स्पेस, पार्क फॉरेस्ट या वुडी एरिया वेस्ट लैंड या वॉटर बॉडी हेतु ग्रीन जॉब्स का सेट तैयार किया जाए।
3. **देखभाल कार्यक्रम** - इसके अलावा बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल हेतु, दिव्यांग श्रमिक वर्ग भी नियुक्त किए जा सकते हैं।
4. **निगरानी कार्यक्रम** - उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को कुशल व प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम लागू किया जाए। नगरपालिका कार्यालयों सरकारी स्कूलों प्रशासनिक कार्यों और पर्यावरणीय मानकों की निगरानी हेतु कार्यक्रम चलाए जाए, तथा वेतन प्रति दिन के हिसाब से 150 रु. तथा 13,000 प्रति माह निर्धारित किया जाए।

अन्य उपाय-

- पहली श्रेणी के उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए तथा दूसरी श्रेणी के सीमित शिक्षा प्राप्त युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए।
- एक अनुमान के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष (1.7-2.7)% खर्च होता है, और लगभग 30-50 मिलियन श्रमिकों को काम के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- 74वें संविधान संशोधन नगरपालिका समितियों की भागीदारी द्वारा शहरी स्थानीय प्रशासन को चलाया जाए।
- मजबूत पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए आरटीआई को धारा-4 के अनुसार सामाजिक लेखा, जनसुनवाई तथा प्रतिक्रियात्मक उपायों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए।
- एक शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम से न केवल श्रमिकों की आय में सुधार होगी बल्कि अर्थव्यवस्था में भी कई गुना वृद्धि होगी।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. शहरी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% है।
2. 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को शहरी स्थानीय स्वशासन हेतु अधिकार प्रदान किये गये थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2
- (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- भारत के आर्थिक विकास में शहर व कस्बे 'विकास इंजन' के रूप में कार्य करते हैं परंतु इस इंजन की गति पर बेरोजगारी एक गतिअवरोधक के रूप में दिखाई दे रहा है। इस कथन के संदर्भ में शहरी बेरोजगारी का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा तथा इसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें।